भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2002

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

ग्रामीण कारीगरों की सहायता के लिए पहल

2002. श्री देवेश शाक्यः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एटा के जलेसर में बड़े पैमाने पर संचालित पीतल के पारंपरिक कास्टिंग उद्योग और कासगंज के ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उनके लिए एक विशेष सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इन ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर वैश्विक ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्पादन निधि (स्फूर्ति) के अंतर्गत तैयार की गई किसी विशेष कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इन दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने शिक्षित युवाओं को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण और राजसहायता प्रदान की गई है; और

(घ) क्या सरकार बिजली की उच्च लागत के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे इन ग्रामीण लघु उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए कोई विशेष सौर ऊर्जा राजसहायता योजना लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय को एटा के जलेसर में पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे पीतल ढलाई उद्योग और कासगंज में ग्रामीण कारीगरों से एक विशेष एमएसएमई हब स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव/कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) : विगत 2 वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में एटा और कासगंज जिलों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सहायता प्राप्त ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, उन्हें संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और उनके अनुमानित सृजित रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	एटा		कासगंज	
	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
2024-25	45	101.26	35	86.02
2025-26	25	95.03	36	114.96

(घ) : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) रूफटॉप सोलर स्थापित करने और एक करोड़ परिवारों के लिए प्रत्येक माह 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

*****